क्या कोयले का संकट खत्म हो गया है?

लेखक- अनिल स्वरूप (पूर्व सचिव, भारत सरकार)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

21 अक्टूबर, 2021

भारत में कोयले की आपूर्ति, माँग से काफी कम है।

प्रारंभ में, इस पर एक बड़ी बहस हुई कि क्या कोयला संकट था। हम अब कोयले पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसलिए, क्या कोई संकट नहीं था? या, अगर कोई था, तो क्या यह सब खत्म हो गया है?

"संकट" एक व्यक्तिपरक शब्द है। संकट है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ मानदंड नहीं हैं। हालांकि, "कमी" को निष्पक्ष रूप से निर्धारित किया जा सकता है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि भारत में कोयले की आपूर्ति मांग से काफी कम है। जबकि मांग लगभग एक अरब मिलियन टन है, देश के भीतर आपूर्ति 800 मीट्रिक टन से कम है। जब यह कमी तीव्र हो जाती है, तो बिजली संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता के मामले में इसे कभी-कभी *'संकट'* कहा जाता है। तीव्र कमी उत्पादन, बढ़ी हुई मांग या आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की विफलता के कारण हो सकती है। जब पिट हेड पर स्टॉक पर्याप्त होते हैं लेकिन बिजली संयंत्रों को आवश्यक आपूर्ति नहीं की जाती है।

मुख्य रूप से कोयला उत्पादन में कमी के कारण देश में कोयला संकट बार-बार आता रहता है। विडंबना यह है कि भारत 300 अरब मीट्रिक टन कोयले पर बैठा है और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। कि हमारी वार्षिक आवश्यकता लगभग एक अरब मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। 2014 में भी ऐसा ही संकट आया था। उस समय, यह एक प्रशासनिक रिपोर्ट के कारण था। तब देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी गणना से इसे संकट बना दिया था। इसके विनाशकारी परिणाम हुए और कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ। तब संकट को सावधानीपूर्वक योजना और निष्पादन के माध्यम से प्रबंधित किया गया था।

तत्काल कोयला संकट को महामारी के बाद आर्थिक सुधार, कोयले की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि, बेमौसम बारिश और देश के भीतर आपूर्ति श्रृंखला के कुप्रबंधन के कारण बिजली की मांग में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। जाहिर है, कि इसमें से कुछ का प्रबंधन कर लिया गया है और हम अब संकट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा कोयले के उत्पादन में ठहराव की बात कोई नहीं कर रहा है। पिछले तीन वर्षों से उत्पादन केवल 600 मीट्रिक टन रहा है। अगर उत्पादन 2014-16 के दौरान जिस दर से (8-9%) बढ़ रहा था, उस दर से बढ़ता, तो सीआईएल का वर्तमान उत्पादन 750 मीट्रिक टन से अधिक होना चाहिए था। गैर-सीआईएल डोमेन से स्थिर कोयला उत्पादन पर भी चर्चा नहीं की जा रही है।

सीआईएल के अलावा अन्य संस्थाओं को भी कई खदानें आवंटित की गईं। इन खदानों ने कोयला उत्पादन क्यों नहीं बढ़ाया? गैर-सीआईएल कोयला उत्पादन 2019-20 में 128 मीट्रिक टन से गिरकर 2020-21 में 120 मीट्रिक टन हो गया। आयातित कोयले पर निर्भरता बढ़ी और इसलिए, जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ीं, जैसा कि उन्होंने हाल ही में कहा, ***''यह एक संकट बन गया है।''***

यदि कोयला उत्पादन नहीं बढ़ाया गया तो संकट फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसे में कोयले का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है? कुछ जवाब 2014-16 के दौरान हुई घटनाओं में निहित हैं।

समर्थित किंतु निगरानी नहीं :-

सीआईएल की एक शानदार टीम है। *इसका 'समर्थन' करने की आवश्यकता है न कि 'निगरानी' की।* इसमें केंद्र सरकार की अहम भूमिका है। सीआईएल को खनन पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी अधिकारियों को राज्यों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार और राज्यों के बीच चल रहे इस "युद्ध" को रोकना होगा। विडंबना यह है कि सभी कोयला गैर-एनडीए दलों द्वारा शासित राज्यों में स्थित है। केंद्र सरकार के अधिकारियों को राज्यों के पास जाना होगा, एक मूल्य प्रस्ताव देना होगा और भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठना होगा। 2014-16 के दौरान दिल्ली में राज्यों के साथ एक भी बैठक नहीं हुई। सभी बैठकें राज्य मुख्यालय में हुई। केंद्र सरकार को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ मंजूरी संबंधी मुद्दों को भी उठाना होगा।

सीआईएल, जिसके पास 2015 में लगभग ₹35,000 करोड़ का भंडार था, अब धन के लिए तंगी है, विशेष रूप से नकदी प्रवाह के रूप में बिजली पैदा करने वाली कंपनियों (जेनको) पर सीआईएल को ₹20,000 करोड़ से अधिक का बकाया है। मौजूदा खदानों के विस्तार के साथ-साथ नई खदानों को खोलने के लिए भी फंड की व्यवस्था करनी होगी। सबसे पहले, केंद्र सरकार को सीआईएल से अधिक धन निकालना बंद करना चाहिए जैसा कि उसने पिछले कुछ वर्षों के दौरान लाभांश के रूप में अपने स्वयं के बजट को संतुलित करने के लिए किया है, जब इस धन का उपयोग नई खदानों को खोलने और मौजूदा लोगों के विस्तार के लिए किया जाना चाहिए था। दूसरा, उसे 'जेनको' पर बकाया राशि के बदले सीआईएल को नकद उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए। गैर-सीआईएल उत्पादन को बढ़ाना होगा। एक अंतर-मंत्रालयी कोयला परियोजना निगरानी समूह (सीपीएमजी) था, जिसे 2015 में त्वरित मंजूरी के लिए स्थापित किया गया था, जो निष्क्रिय हो गया। इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता होगी।

कोयला संकट अस्थायी रूप से समाप्त हो सकता है, लेकिन यदि संकट के मूल सिद्धांतों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। यह भी देखने की जरूरत है कि बिजली क्षेत्र में वित्तीय संकट पैदा हो रहा है। जेनको को वितरण कंपनियों से ₹2,00,000 करोड़ से अधिक की प्राप्य राशि है। बदले में, उन पर CIL का 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। इसलिए, एक गंभीर नकदी संकट है, हालांकि इनमें से अधिकांश संस्थाएं अपनी बैलेंस शीट में लाभ दिखाती हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. भारत मे वर्तमान कोयला संकट को लेकर निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सत्य हैं?

(a) कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा पिछले तीन वर्षों में कोयले के उत्पादन में बढोत्तरी हुई है।

(b) गैर-कोल इंडिया लिमिटेड स्रोतों से कोयला उत्पादन में कमी आयी है।

(c) भारत की वार्षिक कोयले की मांग लगभग एक मिलियन टन है।

(d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Which of the following statement is true regarding the current coal crisis in India?

(a) There has been an increase in the production of coal by Coal India Limited in the last three years.

(b) Coal production from non-Coal India Limited sources has come down.

(c) India's annual coal demand is about one million tons.

(d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. "भारत मे कोयला संकट केन्द्र सरकार की नीतिगत असफलताओं एवं इसके वैश्विक मूल्यों में बढोत्तरी का समन्वित परिणाम है।" इस कथन का परीक्षण कीजिए।

(250 शब्द)

Q. "The coal crisis in India is a collective result of policy failures of the central government and increase in its global prices." Examine this statement. (250 Words)

Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।